[2016] 4 एससीआर 890

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य

बनाम

एसएलएल - एसएमएल (संयुक्त उद्यम कंसोर्टियम) और अन्य।

(2016 की सिविल अपील संख्या 8004)

अगस्त 17, 2016

[मदन बी. लोकुर और आर. के. अग्रवाल, न्यायमूर्ति द्वै]

अनुबंध: बोली प्रक्रिया - एनआईटी की शर्तें - स्वीकार्यता से विचलन - निर्धारित : एनआईटी की अवधि आवश्यक है या नहीं, नियोक्ता द्वारा लिया गया एक निर्णय है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए - भले ही शर्त आवश्यक हो, कर्मचारी के पास इससे विचलित होने का अंतर्निहित अधिकार है बशर्ते कि विचलन सभी बोलीदाताओं और संभावित बोलीदाताओं पर लागू हो - हालांकि; यदि इस शब्द को कर्मचारी द्वारा सहायक या पूरक माना जाता है, तो भी उस निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए _

वर्तमान मामले में, नियोक्ता ने प्रस्तुत करने के लिए बैंक गारंटी का एक विशेष प्रारूप निर्धारित किया - ऐसे मामले में, बोलीदाता को चाहिए .यदि हां, तो क्या सरकार ने केवल उसी विशेष प्रारूप में बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी चाहिए न कि किसी अन्य प्रारूप में

प्रशासनिक कानून: प्रशासनिक कार्रवाई - न्यायिक समीक्षा, गुंजाइश - अभिनिर्धारित प्रशासनिक कार्रवाई में हस्तक्षेप करने में न्यायिक संयम होना चाहिए - आमतौर पर, प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय की गम्भीरता पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया निश्चित रूप से न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकती है।

आधिकारिक मत /सिद्धांत: भागीदारी का विशेषाधिकार सिद्धांत - की व्यवहार्यता

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय

अभिनिर्धारित:- नियम और शर्तों से विचलन तब तक स्वीकार्य है जब तक कि सामानता बनाए रखा जाता है और इसके परिणामस्वरूप कोई मनमानापन या भेदभाव नहीं होता है। रमना मामले में यह कहा गया था कि यदि अन्य बोलीदाताओं को पता था कि पात्रता शर्त को पूरा न करना विचार के लिए बाधा नहीं होगा, तो उन्होंने भी

एक निविदा प्रस्तुत की होगी, लेकिन पात्रता शर्त के कारण उन्हें ऐसा करने से रोका गया था। वर्तमान मामले में, अन्य बोलीदाता और जिन्होंने बोली नहीं लगाई थी, वे बहुत अच्छी तरह से तर्क दे सकते हैं कि यदि वे जानते थे कि

890

बैंक गारंटी प्रारूप अनिवार्य नहीं थी या एनआईटी या जीटीसी 891
की कुछ अन्य शर्तें अनुपालन के लिए अनिवार्य नहीं थीं, वे भी
बोली प्रक्रिया में सार्थक रूप से भाग लेते। दूसरे शब्दों में, A
गोलपोस्ट को फिर से व्यवस्थित करके, उन्हें भागीदारी के
विशेषाधिकार से वंचित कर दिया गया था। [पैरा 36, 381 [899-
ई, एच; 900-ए, ई]

2.एन आई टी और जी टी सी के नियम और शर्तो का
पालन करने के लिए सी सी एल द्वारा लिया गया निर्णय B
निश्चित रूप से किसी भी तरह से तर्कहीन नहीं था या किसी
का पक्ष लेने का इरादा नहीं था। निर्णय वैध था और अनुचित
नहीं था। [पैरा 44] [904-ए-बी]

*रमना दयाराम शेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटीआफ इंडिया
(1979) 3SCC 489:1979

(3) SCR1014; जी जे फर्नांडीज वी। (1) एससीआर 229; टाटा सेलुलर वी। भारत संघ (1994) 6 एससीसी 651 : 1994 (2) कोमल एससीआर 122; जगदीश मंडल वि. उड़ीसा राज्य (2007) 14 एससीसी 517: 2006 (10) सप)। एससीआर 606; मिशिगन रबर (भारत) Lbnited वी.
कर्नाटक राज्य। (2012) 8 एससीसी 216: 2012 (8) एससीआर 128; नजीर अहमद बनाम किंग सम्राट एआईआर 1936 पीसी 253 - पर भरोसा किया।

रश्मि मेटालिक्स लिमिटेड बनाम कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण (2013) 10 एससीसी 95: 2013 (17) एससीआर 345 - प्रतिष्ठित।

पोद्दार स्टील कॉर्पोरेशन बनाम गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स (1991) 3 एससीसी 273: 1991 (2) एससीआर 696; बख्शी सुरक्षा और कार्मिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम देवकिशन कम्प्यूटेड प्राइवेट लिमिटेड (2007) 14 एससीसी 517 : 2006 (10) पूरक एससीआर 606 - संदर्भित।

केस लॉ संदर्भ

1991 (2) एससीआर 696 पैरा 25 2013 को भेजा गया

(17) एससीआर 345 विशिष्ट पैरा 25

1979 (3) एससीआर 1014पर भरोसा किया पैरा 35

1990 (1) एससीआर 229पर भरोसा किया पैरा 38

1994 (2) पूरक एससीआर 122पर भरोसा कियापैरा 42

2006 (10) पूरक SCR 606 पर भरोसा पैरा 42

2006 (10) पूरक एससीआर 606 को संदर्भित किया गया पैरा 46

2012 (8) एससीआर 128 पर भरोसा किया पैरा 46

एआईआर 1936 पीसी 253पर भरोसा किया पैरा 52

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2016 की सिविल अपील संख्या 8004।

2015 के एलपीए संख्या 625 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 26-10-2015 से के साथ

सीए नंबर 8005/2016।

मुकुल रोहतगी,एजी जगदीप धनखड़, ध्रुव मेहता, डॉ. एएम सिंघवी, सीनियर एडवोकेट, राजीव एस. रॉय, अवरोज्योति चटर्जी, अभिजीत एस. रॉय, आदित्य मेहरोत्रा, प्रणब कुमार मलिक, एम. आर. सुकुमार, एम. चंदोला, सी राजेश कुमार, अनन्या कुमार, दिव्यम अग्रवाल, सुश्री स्नेहा सेठ, अखिल भारद्वाज, एमसी ढींगरा, कौशिक पोद्दार, दीपक सभरवाल, चंद्रशेखर विश्वास, एडवोकेट उपस्थित होने वाले पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निर्णय किसके द्वारा दिया गया था?

मदन बी. लोकुर, जे. पहली अपील सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की है। अपील में पहला प्रतिवादी एसएलएल-एसएमएल एक संयुक्त उद्यम परिसंघ है जिसकी बोली सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि द्वारा निविदा आमंत्रण के लिए जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में अस्वीकृत कर दी गई थी।

2. दूसरी अपील पीएलआर-आरपीएल-एसएमएएसएल द्वारा की गई है, जो एक संयुक्त उद्यम है जिसकी बोली सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि द्वारा जारी निविदा ई आमंत्रण संबंधी उसी नोटिस के प्रत्युत्तर में सबसे कम थी और उस बोली को स्वीकार कर लिया गया था।

3. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और पीएलआर-आरपीएल-एसएमएएसएल दोनों ही दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 के निर्णय और आदेश से व्यथित है द्वारा जो झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक माननीय उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय में सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि द्वारा एसएलएल-एसएमएल की बोली की अस्वीकृति को रद्द कर दिया था।

4. हमारे विचार के लिए प्रश्न सामान्य रूप से प्रस्तुत किया गया है या नहीं सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि की बोली प्रक्रिया में बोली दस्तावेजों में निर्धारित फार्मेट में बैंक गारंटी एक अनिवार्य आवश्यकता है और क्या विशेष रूप से सेन्ट्रल जी कोलफील्ड्स लि के बोली दस्तावेजों में निर्धारित फार्मेट में बैंक गारंटी के साथ न भेजी गई बोली को बोली प्रक्रिया को शासित करने वाले सामान्य नियम और शर्तों के खंड 15.2 को ध्यान में रखते हुए गैर-उत्तरदायी माना जा सकता है। सामान्य और विशिष्ट प्रश्न का उत्तर हां में है।

तथ्य:-

5. 5 अगस्त, 2015 को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (संक्षेप में)

(संयुक्त उद्यम संघ) [मदन बी. लोकुर, जे.]

सीसीएल ने निविदाएं आमंत्रित करते हुए एक अधिसूचना जारी की (संक्षेप में एनआईटी के लिए)। इस कार्य का नाम था ओवरबर्डन रिमूवल (1050.00 लीटर घनमीटर) और कोयला निष्कर्षण (975.00 लीटर टीई) के लिए आउटसोसग और 8 वर्ष की अवधि के लिए अशोक ओसीपी, पिपरवार क्षेत्र में सतही खनिक तैनात करके परिवहन।

6. नोटिस में एनआईटी और ऑनलाइन के विवरण का उल्लेख किया गया है प्रस्तुतियाँ, एक इच्छुक व्यक्ति देख सकता सकता है https://eps.buyjunction.in.

7. उपर्युक्त वेबसाइट पर, ई-निविदा का विवरण उपलब्ध कराया गया था, जिसमें कार्य के आगे के विवरण शामिल थे। यह कहा गया था कि निविदाएं अनुभवी ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत की जा सकती हैं, जिनके पास नियंत्रक द्वारा अधिकृत किसी भी एजेंसी से जारी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र है।

प्रमाणन प्राधिकरण, भारत सरकार का। इसका उल्लेख इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिस किसी के पास डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र है वह कम्प्यूटर निरक्षर नहीं हो सकता।

8. ई-निविदा के खंड 3 में "ईएमडी जमा" शीर्षक था और इसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"बयाना राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा की जा सकती है D
(डीडी)/बैंकर चेक (बीसी)/बैंकर पेऑर्डर (बीपीओ) किसी से भी
अनुसूचित बैंक "सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड" के पक्ष में आहरित "रांची" पर देय।

बोली दस्तावेज में दिए गए फार्मेट में किसी भी अनुसूचित बैंक से अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में भी ईएमडी जमा किया जा सकता है। बाहरी बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी उनकी स्थानीय शाखा अर्थात रांची में परिचालित होगी। की वैधता ऐसी बीजी की वैधता बोली की वैद्यता से कम से कम 90 दिन अधिक होनी चाहिए। बोली। बयाना राशि (ईएमडी) का मूल्य 5.00 लाख रुपये से अधिक होने पर ही बीजी स्वीकार्य होगा।

9. उपर्युक्त से महत्वपूर्ण बात यह है कि बयाना राशि जमा किसी भी अनुसूचित बैंक से "बोली दस्तावेज में दिए गए प्रारूप में" एक अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के रूप में की जानी आवश्यक थी।

10. ई-निविदा के खंड 4 में उल्लेख किया गया है कि बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स एमजंक्शन सवसेज लिमिटेड जिसका पता, संपर्क व्यक्ति और ई-मेल दस्तावेज में दिए गए थे, से ऑन-लाइन स्पष्टीकरण मांग सकता है।

एनआईटी के लिए सामान्य नियम और शर्तें (लघु जीटीसी के लिए) [2016] पर एक आगंतुक और संभावित बोलीदाता के लिए भी उपलब्ध कराए गए थे

एक वेबसाइट। जीटीसी का शीर्षक 'सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के क्षेत्रों में ओवरबर्डन हटाने, कोयले की निकासी, परिवहन और लोडिंग के लिए उपकरणों को किराए पर लेना' था।

12. जीटीसी के पैरा । । में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि बयाना राशि की बोली सुरक्षा को उपयुक्त रूप में जमा किया जाना आवश्यक था और उसके पैराग्राफ 15.2 में यह विशेष रूप से कहा गया था कि स्वीकार्य बोली प्रतिभूति/बयाना धन जमा के साथ नहीं होने वाली किसी भी बोली को गैर-उत्तरदायी के रूप में अस्वीकार कर दिया जाएगा।

13. सीसीएल के अनुसार, इसे निविदा के प्रत्युत्तर में आईएल बोलियां प्राप्त हुई थीं, जिसमें एसएलएल-एसएमएल, एक संयुक्त उद्यम परिसंघ (संक्षेप में जेवीसी) सहित निविदा के जवाब में 11बोलियां प्राप्त हुई एक बोली को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। बोलीदाताओं में से नौ ने जीटीओ में प्रदत्त प्रावधान के अनुसार बैंक गारंटी प्रस्तुत की। जे वीसी द्वारा एक बैंक गारंटी प्रदान की गई थी - निर्धारित प्रोफोना में नहीं बल्कि जीटीसी में प्रदान किए गए कुछ अन्य अनुबंध के संबंध में एक अन्य प्रारूप में, जिसका शीर्षक "शासी केंद्रीय कोयला क्षेत्रों के क्षेत्रों में संविदात्मक परिवहन और लोडिंग सीमित"।

14. सीसीएल की ओर से 11 सितम्बर 2015 को जे वीसी को एक इमेल भेजा गया कि उसकी बोली को इस आधार पर रद्द कर दिया गया है कि उसके दस्तावेज अपूर्ण थे सूचित किया गया था कि उन्हें मूल्य बोली खोलने में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15. जवाब में, जे वीसी ने एक ईमेल 15 सितम्बर 2015 को सीसीएल को भेजा जिसमे सूचित किया गया था कि एनआईटी के अंतर्गत यथा निर्धारित सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हैं। 20 इसलिए जे वीसी अपनी बोली खारिज होने का कारण नहीं समझ पा रहे थे। सीसीएल की ओर से उसी दिन ईमेल का जवाब दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि जेवीसी द्वारा दी गई बोली रद्द कर दी गई थी क्योंकि जमा की गई बैंक गारंटी जीटीसी के साथ पठित एनआईटी में दिए गए प्रारूप में नहीं थी।

विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही:

16. अपनी बोली की अस्वीकृति और सी सी एल की प्रतिक्रिया से व्यथित होकर, जेवीसी ने झारखंड उच्च न्यायालय में 2015 की डब्ल्यूपी (सी) संख्या 4559 के रूप में एक रिट याचिका दायर की। दिनांक 7 अक्टूबर, 2015के एक निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया।

17. विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष JBC की ओर से दो प्रस्तुतियां की गई थीं। वो थे:-

H (i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने बैंक गारंटी के लिए कोई फार्मेट निर्धारित नहीं किया था। (संयुक्त उद्यम संघ) [मदन बी. लोकुर, जे.]

इसके अलावा, जीटीसी में बयाना धन जमा/बोली प्रतिभूति के लिए बैंक गारंटी प्रो फॉर्मा लगभग जेवीसी द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी के समान है और इसलिए, इसकी बोली को सीसीएल द्वारा गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया गया था।

(ii) बैंक गारंटी फार्मेट और ई-निविदा के खंड 3 में यह अनिवार्य शर्त है कि बैंक गारंटी रांची में अप्रतिसंहरणीय और देय होनी चाहिए और न्यूनतम वैधता अवधि 90 दिनों से अधिक होनी चाहिए। इन शर्तों को जेवीसी द्वारा पूरा किया गया था।

D

18. यह भी तर्क दिया गया था कि न केवल बैंक गारंटी बुनियादी आवश्यकताओं के अनुरूप थी, बल्कि इसकी शर्तें सीसीएल द्वारा निर्धारित बैंक गारंटी से सख्त थीं। आगे यह तर्क दिया गया था कि किसी भी स्थिति में निर्धारित प्रारूप में बैंक गारंटी प्रस्तुत करना अनुबंध की एक गैर-आवश्यक शर्त थी और इसलिए केवल इस आधार पर जेवीसी की बोली को अस्वीकार करना कि बैंक गारंटी निर्धारित प्रारूप में नहीं थी, मनमाना और अनुचित था।

19. विद्वान एकल न्यायाधीश ने जे वीसी की प्रस्तुतियों पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि निर्धारित प्रारूप के अलावा एक अलग प्रारूप में बैंक गारंटी प्रस्तुत करने से कई समस्याएं पैदा होंगी और यह निश्चित रूप से उचित नहीं था।

20. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह भी निर्णय दिया गया कि एनआईटी की कड़ी शर्तों के साथ-साथ बैंक गारंटी के लिए निर्धारित प्रारूप का पालन करना आवश्यक है।

21. इस तर्क के संबंध में कि एनआईटी ने कोई प्रारूप निर्धारित नहीं किया था, विद्वान एकल न्यायाधीश का विचार था कि यदि जे वीसी को इस संबंध में कोई संदेह था तो उसे एनआईटी में उल्लिखित स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था। चूंकि जे वीसी ने ऐसा नहीं किया, इसलिए बैंक गारंटी के प्रारूप से संबंधित किसी भी संदेह के बारे में आपत्ति उठाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी।

22. जेवीसी के सभी निवेदनों पर विचार करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि रिट याचिका को खारिज करने के लिए पर्याप्त कारण थे।

23. पीड़ित महसूस करते हुए, JVC ने पहले एक पत्र पेटेंट अपील को प्राथमिकता दी उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच 2015 की एलपीए संख्या 625 है। द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 26वां अक्टूबर, 2015 झारखंड उच्च न्यायालय की पीठ ने अपील की अनुमति दी।

डिवीजन बेंच के समक्ष कार्यवाही

24. संयुक्त उद्यम समिति द्वारा खंडपीठ के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि एनआईटी अस्पष्ट है और प्रारूप के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं थी

[20! 6]

ऐसा विवरण जिसमें बैंक गारन्टी प्रस्तुत की जानी अनिवार्य हो । इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया था कि किसी भी स्थिति में सीसी एल द्वारा आवश्यक बैंक गारंटी की आवश्यक शर्तों का पर्याप्त अनुपालन किया गया था। इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि सीसीएल को स्वीकार्य होने के लिए बैंक गारंटी के लिए पांच आवश्यकताएं थीं और जे वीसी ने इन सभी को पूरा किया . उच्च न्यायालय में जे वीसी द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताएं, थीं:

(a) बैंक गारंटी अपरिवर्तनीय होनी चाहिए।

(b) बैंक गारंटी किसी भी अनुसूचित बैंक से होनी चाहिए।

(c) बैंक गारंटी जारीकर्ता बैंक की स्थानीय शाखा, जो रांची में है, में देय होनी चाहिए।

(d) बैंक गारंटी की वैधता बोली की वैधता से कम से कम 90 दिन अधिक होनी चाहिए।

(e) बैंक गारंटी केवल तभी स्वीकार्य होगी जब बयाना जमा राशि का मूल्य 5 लाख रुपये से अधिक हो।

25. उच्च न्यायालय ने विद्वान एकल न्यायाधीश के इस विचार को उलट दिया कि निर्धारित प्रारूप में बैंक गारंटी प्रस्तुत करना एनआईटी का एक गैर-आवश्यक शर्त था। उच्च न्यायालय द्वारा पोद्दार स्टील कॉर्पोरेशन बनाम गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स पर भरोसा किया गया था [1] और रश्मि मेटालिक्स लिमिटेड बनाम कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण[2] यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि चूंकि निर्धारित प्रारूप में बैंक गारंटी प्रस्तुत करना एनआईटी की एक गैर-आवश्यक शर्त थी, इसलिए A जेवीसी की बोली पर विचार किया जाना चाहिए।

26. इसके अतिरिक्त, यह माना गया कि चूंकि सीसीएल द्वारा निर्धारित प्रारूप में बैंक गारंटी की आवश्यकता का पर्याप्त अनुपालन किया गया था, इसलिए जेवीसी की बोली की अस्वीकृति अनुचित थी। यह इसलिए अधिक था क्योंकि जेवीसी द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी में सीसीएल द्वारा निर्धारित फॉर्म में बैंक गारंटी की तुलना में सख्त शर्तें थीं।

27. उपर्युक्त विचारों के मद्देनजर, उच्च न्यायालय की राय थी कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने जेवीसी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने में गलती की थी। उच्च न्यायालय ने सीसीएल द्वारा भेजे गए संचार पत्रों को भी रद्द कर दिया जिसमें जे वीसी की बोली को खारिज कर दिया गया था और इसे भाग लेने की अनुमति दी गई थी - - रिवर्स बोली प्रक्रिया।

[1] (1991) 3 एससीसी 273

H [2] (2013) 10 एससीसी 95

(संयुक्त उद्यम संघ) [मदन बी. लोकुर, जे.]

28. यह इन परिस्थितियों में है कि वर्तमान अपील हमारे समक्ष दायर की गई है।

29. **विचार-विमर्श:-** इस मामले के बारे में असाधारण बात यह है कि नियोक्ता, जो कि सीसीएल है, एनआईटी और जीटीसी द्वारा जारी जीटीसी की शर्तों का पालन करना चाहता है, लेकिन जे वीसी का निवेदन यह है कि सीसीएल को वास्तव में इन दस्तावेजों की शर्तों से विचलित होना चाहिए ताकि जेवीसी को लाभ मिल सके। वास्तव में, एक विशिष्ट आवश्यकता के बावजूद कि बैंक गारंटी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए, जे वीसी इस आधार पर इस संबंध में विचलन के लिए एक पात्रता का दावा करता है कि निर्धारित प्रारूप एनआईटी और जीटीओ का एक गैर-आवश्यक शब्द था। अनिवार्यता के इस मुद्दे का निर्णय कौन करेगा? क्या सीसीएल, जिसके साथ सफल बोलीदाता द्वारा संविदा की जानी है, का इस मामले में कोई अधिकार नहीं है? इसका विज्ञापन करने से पहले, कुछ परिस्थितियों पर स्पष्टता प्राप्त करना आवश्यक है।

30. मामले का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिसकी सराहना की जानी चाहिए, वह यह है कि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जे वीसी निश्चित रूप से कंप्यूटर निरक्षर नहीं थे। प्रत्येक बोलीदाता की तरह, एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र होना आवश्यक था जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि किसी भी बोलीदाता (जेवीसी सहित) को ई-निविदाओं और ई-निविदा में बोली लगाने के लिए कंप्यूटर के उपयोग के साथ कुछ हद तक सुविधा थी। यह वह परिचितता है जिसने जे वीसी को बैंक गारंटी के प्रारूप को "गलत" तक पहुंचने में सक्षम बनाया। इन परिस्थितियों में, यह बेहद अजीब है कि जे वीसी बैंक गारंटी के सही और निर्धारित प्रारूप तक पहुंचने में सक्षम नहीं था। जे वीसी द्वारा दिया गया बहाना कि एनआईटी अस्पष्ट था और यह स्पष्ट नहीं था कि बैंक गारंटी का निर्धारित प्रारूप क्या था, एक दलदल के अलावा कुछ भी नहीं प्रतीत होता है। जीटीसी और बैंक गारंटी की शर्तों की एक साधारण रीडिंग सही निर्धारित प्रारूप और "गलत" को इंगित करने के लिए पर्याप्त होगी
प्रारूप।

31. दूसरे, दोनों जीटीसी में उल्लिखित शीर्षक अलग-अलग थे। सही जीटीसी में "सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के क्षेत्रों में ओवरबर्डन को हटाने, कोयले की निकासी, परिवहन और लोडिंग के लिए उपकरणों को किराए पर लेना" शीर्षक था, जबकि प्रासंगिक नहीं था जीटीसी ने "सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के क्षेत्रों में गवर्निंग कॉन्ट्रैक्टुमेंटल ट्रांसपोर्टेशन एंड लोडिंग" शीर्षक बोर किया। ओवरबर्डन रिमूवल (1050.00 एल घनमीटर) और कोयला निष्कर्षण (975.00) के लिए आउटसोसग कार्य के लिए बोली लगाने वाले दोनों जीटीसी और कार्य के लिए बोली लगाने वाले किसी भी व्यक्ति के बीच पर्याप्त अंतर है
और अशोक ओसीपी में सतह खनिक को तैनात करके परिवहन, [2016]

8 वर्षों की अवधि के लिए एक पिपरव्वावर क्षेत्र तुरंत देख सकता है कि कौन सा जी टीसी प्रासंगिक है और कौन सा नहीं।

32. इस संदर्भ में और तीसरा, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि यदि जेवीसी को प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारंटी के प्रारूप के संबंध में कोई संदेह था, तो वह एनआईटी में उल्लिखित संबंधित बी प्राधिकरण से स्पष्टीकरण मांग सकता था और मांगना चाहिए था। इसके अलावा, जेवीसी कम से कम सीसीएल को यह अभ्यावेदन दे सकते थे और उन्हें यह अभ्यावेदन देना चाहिए था कि बैंक गारंटी के लिए निर्धारित प्रारूप या तो उपलब्ध नहीं था या एनआईटी अस्पष्ट था या बैंक गारंटी के निर्धारित प्रारूप के संबंध में स्पष्टता का अभाव था। जे वीसी ने न तो कोई स्पष्टीकरण मांगा और न ही सीसीएल को कोई प्रतिनिधित्व दिया। ग को समझना मुश्किल है

हमारे सामने प्रस्तुत स्थिति में जेवीसी का आचरण, विशेष रूप से आठ साल के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपये के अनुबंध के संदर्भ में।

33. हमें विद्वान महान्यायवादी द्वारा सूचित किया गया था कि बोली लगाने वालों में से 9 ने निर्धारित और सही प्रारूप में बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी। इन परिस्थितियों में, हमारी विश्वसनीयता को बढ़ाने के बाद भी, यह समझना अत्यंत कठिन है कि संयुक्त उद्यम कंपनी बैंक गारंटी के लिए निर्धारित प्रारूप तक पहुंचने या निर्धारित प्रपत्र में बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में असमर्थ क्यों थी जबकि प्रत्येक अन्य बोलीदाता ऐसा कर सकता था या वह स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांग सका या यह किसी कथित अस्पष्टता के विरुद्ध प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर सका। बैंक गारंटी के निर्धारित प्रारूप या एनआईटी में कथित जांच के संबंध में जेवीसी की आपत्ति और आचरण पूरी तरह से बोर्ड से परे प्रतीत नहीं होता है।

34. इन अपीलों में मुख्य मुद्दा बोली प्रक्रिया में प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत बोलियों से निपटने के दौरान एनआईटी और जीटीसी की शर्तों का पालन करने में सीसीएल की प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा नहीं है। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या सीसीएल ने जे

वीसी की बैंक गारंटी को इस आधार पर खारिज करने में पर्याप्त रूप से प्रतिकूल रूप से काम किया कि यह निर्धारित प्रारूप में नहीं था, जिससे संवैधानिक न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की मांग की गई और सीसीई के फैसले में हस्तक्षेप किया गया।

35. रणमना दयाराम शेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में: • इस न्यायालय ने माना कि किसी दस्तावेज़ में प्रयुक्त शब्द अनावश्यक या निरर्थक नहीं हैं, लेकिन उन्हें कुछ अर्थ और महत्व दिया जाना चाहिए:

"यह व्याख्या का एक अच्छी तरह से तय नियम है जो समान रूप से लागू होता है

---

[3] (1979) 3 एससीसी 489

(संयुक्त उद्यम संघ) [मदन बी. लोकुर, जे.]

क़ानूनों के रूप में दस्तावेज़, जो सम्मोहक आवश्यकता के लिए बचाते हैं, A न्यायालय को किसी दस्तावेज़ की भाषा को अतिरेक देने के लिए तत्पर नहीं होना चाहिए "और शुरुआत में यह मानने के लिए इच्छुक होना चाहिए कि प्रत्येक शब्द का कुछ प्रभाव हो या कुछ उपयोग हो"। शब्दों को असंवेदनशील के रूप में अस्वीकार करना न्यायिक व्याख्या का अंतिम उपाय होना चाहिए, क्योंकि यह सामान्य ज्ञान पर आधारित एक प्राथमिक नियम है कि औपचारिक दस्तावेज के किसी भी लेखक को दूसरों द्वारा कार्रवाई करने का इरादा नहीं माना जाना चाहिए, बिना अर्थ के शब्दों का उपयोग करने के लिए माना जाना चाहिए। अदालत को, जहां तक संभव हो, ऐसे निर्णय से बचना चाहिए जो दस्तावेज़ के लेखक द्वारा उपयोग किए गए शब्दों को अर्थहीन और निरर्थक बना देगा या दस्तावेज़ के किसी भी हिस्से को चुप कराने और इसे पूरी तरह से अनुपयुक्त बनाने के लिए काम करेगा।

उस मामले में, अभिव्यक्ति "पंजीकृत लिंड क्लास होटल व्यवसायी" को अनुपयुक्त और शायद अव्याकरणिक होने के रूप में मान्यता दी गई थी; फिर भी, सामान्य ज्ञान एक व्यक्ति को चलाने का वर्णन करने में नाराज नहीं था ।पंजीकृत इल ग्रेड होटल एक पंजीकृत आईएल क्लास होटल व्यवसायी के रूप में। इसके पक्ष में इस निर्णय के बावजूद, उस मामले में उत्तरदाताओं को बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए तथ्यात्मक रूप से अयोग्य माना गया था।

36. यह आगे आयोजित किया गया था कि यदि अन्य (जैसे कि उस मामले में अपीलकर्ता) को पता था कि पंजीकृत आईएल क्लास होटल व्यवसायी होने की पात्रता शर्त को पूरा न करना विचार के लिए एक बार नहीं होगा, तो उन्होंने भी एक निविदा प्रस्तुत की होगी, लेकिन पात्रता शर्त के कारण ऐसा करने से रोका गया था, जिसे उत्तरदाताओं के मामले में आराम दिया गया था 4. इसके परिणामस्वरूप उत्तरदाताओं 4 के पक्ष में असमान व्यवहार हुआ - उपचार जो संवैधानिक रूप से अनुमेय था। इस पर विस्तार से, यह आयोजित किया गया था:

> "यह वास्तव में अकल्पनीय है कि कानून के शासन द्वारा शासित लोकतंत्र में, कार्यकारी सरकार या उसके किसी भी अधिकारी के पास व्यक्ति के हितों पर मनमानी शक्ति होनी चाहिए। कार्यकारी सरकार के प्रत्येक कार्य को तर्क के साथ सूचित किया जाना चाहिए और मनमानेपन से मुक्त होना चाहिए। यही कानून के शासन का सार है और इसकी न्यूनतम आवश्यकता है। और इस सिद्धांत के आवेदन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या
> शक्ति के प्रयोग में कुछ अधिकार को प्रभावित करना या कुछ विशेषाधिकार से वंचित करना शामिल है। (महत्व दिया गया)

इस सिद्धांत को वर्तमान अपीलों पर लागू करते हुए, अन्य बोलीदाता और जिन्होंने बोली नहीं लगाई थी, वे बहुत अच्छी तरह से तर्क दे सकते हैं कि यदि वे जानते थे कि बैंक गारंटी का निर्धारित प्रारूप अनिवार्य नहीं था या

उत्तर यह कि एनआईटी या जीटीसी के कुछ अन्य शर्त अनुपालन के लिए अनिवार्य नहीं थे, उन्होंने भी बोली प्रक्रिया में सार्थक रूप से भाग लिया होगा। दूसरे शब्दों में, गोलपोस्ट को फिर से व्यवस्थित करके, उन्हें भागीदारी के "प्रिवी लेग" से वंचित कर दिया गया था।

37. जे वीसी के लिए यह कहना कि इसकी बैंक गारंटी निर्धारित प्रारूप की तुलना में सख्त बी शर्तों में थी, न तो यहां है और न ही वहां है। यह नियोक्ता या इस न्यायालय का काम नहीं है कि वह यह निर्धारित करने के लिए प्रत्येक बैंक गारंटी की जांच करे कि यह निर्धारित प्रारूप से अधिक सख्त है या कम कठोर है। तथ्य यह है कि एक प्रारूप निर्धारित किया गया था और इसका पालन न करने का कोई कारण नहीं था। गोलपोस्ट को फिर से व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है या बोली प्रक्रिया के दौरान कुछ के अधिकार को प्रभावित करने या सी से इनकार करने के लिए फिर से व्यवस्थित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

कुछ के लिए एक विशेषाधिकार लाना है

38. जी.जे. फर्नांडीज बनाम कर्नाटक राज्य* के मामले में रमना दयाराम शेट्टी में निर्धारित दोनों सिद्धांतों की पुन पुष्टि की गई। यह पुष्टि की गई कि निविदा जारी करने वाली पार्टी (नियोक्ता) को "समय पर और सख्ती से" निविदा की शर्तों को लागू करने का अधिकार है। यदि कोई पार्टी D

निविदा की शर्तों के सख्त प्रवर्तन से नियोक्ता को रोकने के आदेश के लिए न्यायालय में जाता है, न्यायालय ऐसा करने से इनकार कर देगा। यह भी पुष्टि की गई कि नियोक्ता निविदा के नियमों और शर्तों से विचलित हो सकता है यदि "परिवर्तन सभी इच्छुक आवेदकों को समान रूप से प्रभावित करते हैं और आपत्तिजनक नहीं थे। इसलिए विचलन नियम और शर्तों की अनुमति तब तक है जब तक कि समान अवसर बनाए रखा जाता है और इसके परिणामस्वरूप रमण दयाराम शेट्टी अर्थ में कोई मनमानापन या भेदभाव नहीं होता है।

39. पोद्दार स्टील एक दिलचस्प मामला था और इसने प्रवचन में एक नया आयाम जोड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

रिकॉर्ड करता है कि एनआईटी में प्रासंगिक खंड ने बोलीदाता को नकद में या "एसबीआई की डीएलडब्ल्यू शाखा पर सहायक मुख्य कैशियर, डीएलडब्ल्यू / वाराणसी के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट" द्वारा बयाना राशि जमा करने का विकल्प दिया। 5 21 पार्टियों ने एनआईटी को जवाब दिया था, लेकिन उनमें से 8 ने कोई बयाना राशि जमा नहीं की थी और शेष 13 बोलीदाताओं ने "एक या दूसरे तरीके से बयाना राशि जमा की थी, लेकिन जरूरी नहीं कि एनआईटी में प्रदान किए गए

तरीके से शायद कुछ को छोड़कर। निविदा समिति ने एनआईटी की शर्तों से हटकर इन 13 बोलीदाताओं की बोलियों पर विचार किया और पोद्दार की बोली स्वीकार कर ली

---

4 (1990) 2 एससीसी 488

गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स वी। भारत संघ और अन्य। 1990 सभी। एलजे 1 140

पोद्दार स्टील , जिसने नकद या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा नहीं बयाना पैसा दिया था A लेकिन "यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सोनारपुरा, वाराणसी में अपने सी/डी खाते पर एक ढीला चेक आहरित करके। भेदभावपूर्ण व्यवहार के मुद्दे पर, नियोक्ता का तर्क यह था कि चूंकि सभी 13 बोलीदाताओं, जिन्होंने बयाना राशि जमा की थी, के साथ समान व्यवहार किया गया था, इसलिए किसी भी भेदभावपूर्ण व्यवहार का कोई मुद्दा नहीं था।

संभव है कि जिन लोगों ने कोई बयाना राशि जमा नहीं की थी, अगर उन्हें पता होता कि बयाना राशि के लिए एक क्रॉस चेक (एसबीआई के अलावा किसी अन्य बैंक पर आहरित किया गया) नियोक्ता को स्वीकार्य था, तो वे भी चुनाव मैदान में हो सकते थे। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने कहा कि उन्हें प्रतिस्पर्धा से बाहर करना, इस अघोषित विचलन के माध्यम से बोलीदाताओं और संभावित बोलीदाताओं को समान रूप से प्रभावित करना, बोली प्रक्रिया को अनुचित बनाता है। उच्च न्यायालय ने एक "आवश्यक शब्द" अवधारणा पेश की और कहा कि .एनआईटी में बयाना राशि जमा करने से संबंधित खंड इसकी एक अनिवार्य अवधि थी और इसे विचलित नहीं किया जा सकता था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवधारित किया:

> "केवल तथ्य यह है कि सभी निविदाकर्ताओं ने बयाना राशि जमा की थी, चाहे वह खंड 6 के संदर्भ में हो या नहीं, उनके साथ समान व्यवहार किया गया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। यह कल्पना करना बहुत संभव है कि जो पक्ष अग्रिम राशि जमा करने में विफल रहे थे, वे भी मैदान में हो सकते थे, अगर उन्हें पता था कि चेक के माध्यम से बयाना राशि भी स्वीकार्य थी। इस प्रकार वे स्पष्ट रूप से दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने से वंचित हो गए हैं और यह उत्तरदाताओं 1 से 5 की कार्रवाई को अनुचित बनाता है जब एनआईटी की शर्त संख्या 6 विशेष रूप से इंगित करती है कि नकद या डिमांड ड्राफ्ट को छोड़कर किसी अन्य मोड में बयाना धन जमा करना स्वीकार्य नहीं होगा। यह हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए यह एक आवश्यक पूर्व शर्त थी

40. हालांकि, उच्च न्यायालय ने रमण दयाराम शेट्टी और भागीदारी के विशेषाधिकार सिद्धान्त कापालन करते हुए यह विचार किया की यह निविदाए प्रस्तुत करना और उत्तरदाता इससे विचलित होने के हकदार नहीं थे। सभी निविदाएं जिनके साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में दर्शाए गए तरीके से अग्रिम राशि जमा नहीं की गई थी, अस्वीकृत किए जाने के योग्य थीं। हम उत्तरदाताओं के इस तर्क को खारिज करते हैं कि बयाना राशि तब भी स्वीकार की जा सकती है जब इसे एनआईटी में उन लोगों के अलावा किसी अन्य तरीके से जमा किया गया हो। हम यह भी मानते हैं कि एनआईटी का क्लॉज 6 केवल सहायक या अधीनस्थ स्थिति नहीं है, बल्कि जिस भाषा में लिखा गया है, उसे देखते हुए निविदा की एक महत्वपूर्ण और आवश्यक शर्तें थीं, जिनसे विचलित नहीं किया जा सकता था।

D

41 . अपील में, इस न्यायालय ने एनआईटी के आवश्यक और गैर-आवश्यक या सहायक या पूरक शब्दों के सिद्धांत को स्वीकार किया। यह माना गया कि पोद्दार स्टील द्वारा जारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चेक (हालांकि एनआईटी की शर्तों से विचलन) एनआईटी की शर्तों को पूरा करने के लिए पर्याप्त था, शर्त द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मुख्य उद्देश्य के लिए सहायक या पूरक थी और नियोक्ता एनआईटी के बयाना धन खंड के "तकनीकी शाब्दिक अनुपालन" को माफ कर सकता था "विशेष रूप से जब यह उसके हित में था उक्त बोली को अस्वीकार नहीं करना जो सबसे अधिक थी। दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि निविदा दस्तावेज की एक आवश्यक अवधि से विचलित नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक सहायक या पूरक या गैर-आवश्यक शब्द से विचलित किया जा सकता है, और यह कि विचलन संभावित बोलीदाताओं के संदर्भ के बिना हो सकता है।

42 दुर्भाग्य से, इस न्यायालय ने रमना दयाराम शेट्टी में निर्धारित विशेषाधिकार-भागीदारी सिद्धांत का बिल्कुल भी पालन नहीं किया और जीजे फर्नांडीज में स्वीकार किया। दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया कि क्या विचलन के परिणामस्वरूप, अन्य लोग भी बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र हो सकते थे। पोद्दार स्टील में इस सिद्धांत की अनदेखी की गई।

. 43. एक एनआईटी के नियमों और शर्तों से विचलित करने के लिए एक नियोक्ता के निहित अधिकार को स्वीकार करने के अलोक में जारी है, और विशेषाधिकार-भागीदारी सिद्धांत और स्तर खेल फील्ड अवधारणा को फिर से प्रस्तुत करते हुए, इस न्यायालय ने निर्णय लेने की प्रक्रिया पर जोर दिया, विशेष रूप से एक वाणिज्यिक अनुबंध के संबंध में। इस विषय पर अधिक महत्वपूर्ण मामलों में से एक टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ मामले में तीन न्यायाधीशों का निर्णय है। भारत संघ जिसने किसी निर्णय की वैधता को महत्व दिया न कि उसकी गम्भीरता को। यदि कोई प्रशासनिक निर्णय, जैसे कि एनआईटी की शर्तों में विचलन, मनमाना, तर्कहीन, अनुचित, पक्षपातपूर्ण या पक्षपातपूर्ण नहीं है, तो न्यायालय लिए गए निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं करेंगे। इसी तरह, अदालतें तकनीकी या प्रक्रियात्मक उल्लंघन के संबंध में असफल बोलीदाता के इशारे पर निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। यह इस न्यायालय द्वारा (टाटा सेल्युलर के बाद) जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य मामले में स्पष्ट रूप से कहा गया था। उड़ीसा राज्य निम्नलिखित शब्दों में:

उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य मनमानेपन, अतार्किकता, तर्कहीनता, पक्षपात और दुर्भावना को रोकना है। इसका उद्देश्य यह जांचना है कि चुनाव या निर्णय लिया गया है या नहीं

[6] (1994) 6 एससीसी 651

H(2007) 14 एससीसी 517

"कानूनी रूप से" और यह जांचने के लिए नहीं कि पसंद या निर्णय गम्भीर है या नहीं। जब निविदाएं या ठेका देने से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया जाता है, तो कुछ विशेष विशेषताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक अनुबंध एक वाणिज्यिक लेनदेन है। . निविदाओं का मूल्यांकन करना और अनुबंध देना अनिवार्य रूप से है

वाणिज्यिक कार्य। समानता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत दूरी पर रहते हैं। यदि संविदा प्रदान करने से संबंधित निर्णय सदाशयी है और लोकहित में है तो न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप नहीं करेंगे, भले ही किसी निविदाकर्ता के प्रति कोई प्रक्रियात्मक विपथन या मूल्यांकन में त्रुटि या पूर्वाग्रह उत्पन्न हो। रक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति को लागू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी
सार्वजनिक हित की कीमत पर निजी हित, या संविदात्मक विवादों को तय करने के लिए। शिकायत के साथ निविदाकर्ता या ठेकेदार हमेशा सिविल कोर्ट में नुकसान की मांग कर सकता है। काल्पनिक शिकायतों, घायल गर्व और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के साथ असफल निविदाकर्ताओं द्वारा प्रयास, कुछ तकनीकी/प्रक्रियात्मक के तिल से पहाड़ बनाने के लिए
स्वयं के प्रति उल्लंघन या कुछ पूर्वाग्रह, और न्यायिक D
समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके न्यायालयों को हस्तक्षेप करने के लिए राजी करना, का विरोध किया जाना चाहिए। इस तरह के हस्तक्षेप, चाहे अंतरिम हों या अंतिम, सार्वजनिक कार्यों को वर्षों तक रोक सकते हैं, या हजारों और लाखों लोगों को राहत और सहायता में देरी कर सकते हैं और परियोजना लागत को कई गुना बढ़ा सकते हैं।

इस न्यायालय ने तब उन प्रश्नों को निर्धारित किया जो ऐसी स्थिति में पूछे जाने चाहिए। यह कहा गया था:

"इसलिए, न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में निविदा या अनुबंध संबंधी मामलों में हस्तक्षेप करने से पहले अदालत को खुद से निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए:

(i) क्या प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया या किया गया निर्णय दुर्भावनापूर्ण है या किसी का पक्ष लेने का इरादा है

क्या अपनाई गई प्रक्रिया या किया गया निर्णय इतना मनमाना और तर्कहीन है कि अदालत कह सकती है: "निर्णय ऐसा है कि कोई भी जिम्मेदार प्राधिकारी यथोचित और उसके अनुसार कार्य नहीं करता है। जो प्रासंगिक कानून तक पहुंच सकता था";

(ii) क्या जनहित प्रभावित होता है।

यदि उत्तर नकारात्मक हैं, तो अनुच्छेद 226 के तहत कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

904

44. वर्तमान अपीलों में इन प्रश्नों को पूछने पर, यह स्पष्ट है कि सीसीएल द्वारा एनआईटी और जीटीसी के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए लिया गया निर्णय निश्चित रूप से किसी भी तरह से तर्कहीन नहीं था या किसी के पक्ष में इरादा नहीं था। निर्णय वैध था और अनुचित नहीं था।

बी 45. रश्मि मेटालिक्स तुलनात्मक रूप से अलग मामला था क्योंकि एनआईटी का खंड (जे) विचार का विषय था। इस . क्लॉज के तहत बोली लगाने वाले को वैध पैन नंबर, वैट नंबर, नवीनतम आयकर रिटर्न और पेशेवर कर रिटर्न की पावती की प्रति जमा करनी होती है। नियोक्ता ने बोली प्रक्रिया में अर्हता प्राप्त करने के लिए इसे एक आवश्यक शर्त के रूप में व्याख्या की। इस विचार को एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सही ठहराया गया था

और कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच। इस न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में उलट दिया:

"हमें लगता है कि आयकर रिटर्न ने एक आवश्यक शर्त का चरित्र ग्रहण किया होगा यदि योग्यता में से एक था . या तो सकल आय या शुद्ध आय जिस पर कर आकर्षित किया गया था। कई मामलों में यह एक हितकारी शर्त है, क्योंकि यह निविदा इकाई की वाणिज्यिक स्थिति और विश्वसनीयता का संकेत है। यह सुविधा अनुपस्थित होने के कारण, हमें लगता है कि नवीनतम आयकर रिटर्न दाखिल करना एक संपार्श्विक शर्त था, और तदनुसार निविदा प्राधिकरण को इस विसंगति को अपीलकर्ता कंपनी

के ध्यान में लाना चाहिए था और यदि उसके बाद भी कोई सुधार नहीं किया गया था, तो स्थिति सराहनीय रूप से भिन्न हो सकती थी।

अनिवार्य रूप से, इसलिए, इस न्यायालय ने नियोक्ता के लिए अपने दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित किया जिसने एनआईटी के इस शर्त को एफ अनुपालन के लिए अनिवार्य होने की व्याख्या की। रश्मि मेटालिक्स ने पोद्दार स्टील का अनुसरण किया और स्पष्ट रूप से रमण दयाराम शेट्टी, जीजे फर्नांडीज, टाटा सेल्युलर और जगदीश मंडल में निर्धारित उक्ति की अनदेखी की और इसे अपने स्वयं के विशिष्ट तथ्यों तक ही सीमित रहना चाहिए। किसी भी घटना में, यह निर्णय हमारे सामने किसी भी पक्ष के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है।

46. यह सच है कि पोद्दार स्टील और रश्मि मेटालिक्स में इस न्यायालय द्वारा बोली दस्तावेजों में आवश्यक और सहायक शर्तों के बीच अंतर किया गया है। इसी तरह का भेद हाल ही में बख्शी सिक्योरिटी एंड पर्सनेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम देवकिशन कंप्यूटेड प्राइवेट लिमिटेड में किया गया था पोद्दार स्टील में किए गए संदर्भ के माध्यम से

H [8] 2016 (7) स्केल 425

उस मामले में, इस न्यायालय ने Aएनआईटी को आवश्यक के रूप में (नियोक्ता के दृष्टिकोण की पुष्टि करना) और मिशिगन रबर (इंडिया) लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य कर्नाटक राज्य। [9] इसके बाद, इस न्यायालय ने बख्शी सुरक्षा और कार्मिक सेवाओं को निविदा में भाग लेने के लिए अयोग्य ठहराते हुए नियोक्ता के फैसले को चुनौती देने से इनकार कर दिया।

47. इस चर्चा का परिणाम यह है कि बोली या बोलीदाता की स्वीकृति या अस्वीकृति के मुद्दे को न केवल असफल पार्टी के दृष्टिकोण से बल्कि नियोक्ता के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। जैसा कि रमना दयाराम शेट्टी में माना गया है, एनआईटी की शर्तों को निरर्थक या अनावश्यक होने के रूप में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्हें एक अर्थ और आवश्यक महत्व दिया जाना चाहिए। जैसा कि टाटा सेल्युलर में बताया गया है, प्रशासनिक कार्रवाई में हस्तक्षेप करने में न्यायिक संयम होना चाहिए। आमतौर पर, नियोक्ता द्वारा लिए गए

निर्णय की गम्भीरता पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया निश्चित रूप से न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकती है। निर्णय की गम्भीरता पर सवाल उठाया जा सकता है यदि यह तर्कहीन या दुर्भावनापूर्ण है या किसी या निर्णय का पक्ष लेने का इरादा है "जो कि कोई भी जिम्मेदार प्राधिकारी यथोचित रूप से और प्रासंगिक कानून के अनुसार कार्य नहीं कर सकता है जैसा कि जगदीश मंडल एवं निचिगन रबर में निर्धारित है

48. इसलिए, एनआईटी की अवधि आवश्यक है या नहीं, यह नियोक्ता द्वारा लिया गया निर्णय है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। भले ही Eअवधि आवश्यक है, नियोक्ता के पास इससे विचलित होने का अंतर्निहित अधिकार है बशर्ते कि विचलन सभी बोलीदाताओं और संभावित बोलीदाताओं पर लागू किया जाता है जैसा कि रंताना दयाराम शेट्टी में आयोजित किया गया है। हालांकि, अगर नियोक्ता द्वारा इस शब्द को सहायक या सहायक माना जाता है, तो उस निर्णय का भी सम्मान किया जाना चाहिए। उस निर्णय की वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है जैसा कि ऊपर चर्चा किए गए विभिन्न निर्णयों में उल्लेख किया गया है, बहुत सीमित आधार पर, लेकिन निर्णय की गम्भीरता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, अन्यथा यह न्यायालय निविदा जारी करने वाले प्राधिकारी के कार्य को अपने हाथ में ले लेगा, जो वह नहीं कर सकता।

49. पुन नियोक्ता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यदि न्यायालय नियोक्ता के निर्णय लेने के कार्य को अपने हाथ में ले लेते हैं और नियोक्ता के इरादे के विपरीत आवश्यक और गैर-आवश्यक शर्तों के बीच अंतर करते हैं और इस प्रकार व्यवस्था को पुन लिखते हैं, तो इससे सभी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिनमें वह समस्या भी शामिल है जिससे हम जूझ रहे हैं।

(2012) 8 एससीसी 216

उदाहरण के लिए, जी टीसी जिसका हम विशेष रूप से खंड 15.2 में उल्लेख करते हैं, कहता है कि "स्वीकार्य बोली सुरक्षा/ईएमडी के साथ कोई भी बोली नियोक्ता द्वारा गैर-उत्तरदायी के रूप में अस्वीकार कर दी जाएगी। निश्चित रूप से, सीसीएल ने पूर्व दृष्टया इस शब्द को अनिवार्य होने का इरादा किया था, फिर भी उच्च न्यायालय ने

कहा कि बैंक गारंटी को उसके द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह आवश्यकता जीटीओ की एक गैर-आवश्यक शर्त थी। सीसीएल के दृष्टिकोण से, जीटीसी को उच्च न्यायालय द्वारा अनुचित रूप से फिर से लिखा गया है।

50. एक नियोक्ता (जैसे सीसीएल) द्वारा एक और समस्या का सामना किया जा सकता है यदि एनआईटी या जीटीसी के संदर्भ में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का पालन नहीं किया जाता है और इसके सादे अर्थ को त्याग दिया जाता है। c द्वारा एक समस्या का सामना किया जा सकता है

एक नियोक्ता यदि प्रत्येक बोलीदाता एक अलग प्रारूप में बैंक गारंटी प्रस्तुत करता है या जिसके साथ वह सहज है। ऐसी स्थिति में, सीसीएल को यह पता लगाने के लिए प्रत्येक बैंक गारंटी की जांच करनी होगी कि क्या यह अपनी आवश्यकताओं और एनआईटी और जीटीओ को पूरा करता है। बैंक गारंटी के पाठ के अलावा, बोलीदाता द्वारा मामूली बदलाव किए जा सकते हैं जैसे रांची (लेकिन झारखंड में) के अलावा किसी अन्य स्थान पर प्रवर्तनीयता आदि। इससे नियोक्ता पर परिहार्य और अनुचित बोझ पड़ेगा, खासकर यदि बड़ी संख्या में बोलीदाता हैं।

51. इतना ही नहीं, नियोक्ता द्वारा किसी विशेष बैंक गारंटी को स्वीकार या अस्वीकार करने में लिया गया कोई भी निर्णय उसके द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जाता है (परिहार्य) मुकदमेबाजी का कारण बन सकता है जिसमें नियोक्ता को प्रत्येक बैंक गारंटी की अस्वीकृति या स्वीकृति को सही ठहराने की आवश्यकता होती है। यह शायद ही अनुकूल है एक चिकनी और परेशानी मुक्त बोली प्रक्रिया के लिए।

52. एक संपूर्ण सिद्धांत है जिसे न्यायायलय लम्बे समय तक पालन करते रहे है जिसे नजीर अहमद बनाम किंग एम्परर में व्यक्त किया गया था, वह यह है "जहा एक निश्चित काम को निश्चित तरीके से करने के लिए एक शक्ति दी जाती है उसे उसे तरह से किया जाना चाहिए या बिलकुल नहीं आवश्यक परिवर्तन के साथ (म्युटाटीस म्युटेंडीस)बोली दस्तावेजो के लिए आवश्यक परिवर्तन करने के लिए बीस हितकारी सिद्धांत को छोड़ने या न लागू करने के लिए कोई वैध कारण नहीं है

संविदात्मक विवाद, विशेष रूप से वाणिज्यिक अनुबंधों या बोलियों में अग्रणी वाणिज्यिक अनुबंधों के लिए जहां कड़ी प्रतिस्पर्धा है। यह नज़ीर अहमद में निर्धारित सिद्धांत के आवेदन से पालन करना चाहिए

. कि यदि नियोक्ता बैंक गारंटी के एक विशेष प्रारूप को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित करता है, तो एक बोलीदाता को उसमें बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी चाहिए

[10]एआईआर 1936 पीसी 253

केवल विशेष प्रारूप और किसी अन्य प्रारूप में नहीं। हालाँकि, जैसा कि उल्लेख किया गया है इसके अतिरिक्त, इस संबंध में कोई अनम्यता नहीं है और एक नियोक्ता विचलन कर सकता है .बोली दस्तावेज की शर्तों से लेकिन केवल ऊपर उल्लिखित मापदंडों के भीतर।

53. नजीर अहमद का इस न्यायालय और देश के अन्य संवैधानिक न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों में अनुसरण किया गया है। वही Bकेन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दिनांक 31 मार्च, 2006 के अपने परिपत्र में इस सिद्धांत को संशोधित रूप में मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया है सरकार ने दिसम्बर, 2007 से दिसम्बर, 2007 तक की अधिसूचना जारी की है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि सभी संगठनों को बैंक गारंटियां स्वीकार करने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए जो बैंकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुकूल हो। ऐसी ही एक आवश्यकता यह है कि ग बैंक गारंटी उचित निर्धारित प्रारूप में होनी चाहिए और मूल के साथ प्राप्त होने पर शब्दश सत्यापित की जानी चाहिए। शब्दश सत्यापन के इस सिद्धांत का पालन न केवल नियोक्ता के लिए अनुचित समस्याओं से बचाएगा बल्कि नियोक्ता की ओर से व्यक्तिपरकता को भी लगभग समाप्त कर देगा।

54. इस संदर्भ में, और वर्तमान समय में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विश्व बैंक ने अनुबंधों के प्रवर्तन और व्यापार करने में आसानी से संबंधित मामलों में भारत को बेहद नीचे रखा है। दुनिया भर में 1,89 देशों में से, भारत अनुबंधों के प्रवर्तन के मामले में 178 वें स्थान पर है और व्यापार करने में आसानी के मामले में 130 वें स्थान पर है [ली] . हमारे देश को दी गई इस बेहद कम रैंकिंग के संभावित कारणों में से एक एनआईटी और जीटीसी जैसे दस्तावेजों की शर्तों का सख्ती से पालन करने में संबंधित सभी पक्षों की विफलता है। जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान 5 [वां] अगस्त, 2015 को सतह पर था और एक साल बाद, हम अभी भी लगभग 2000 करोड़ रुपये के अनुबंध के लिए बैंक गारंटी की स्वीकृति के मुद्दे से जूझ रहे हैं - निश्चित रूप से यह कोई छोटी राशि नहीं है।

निष्कर्ष :-

55. उपलब्ध केस लॉ के आधार पर, हमारा विचार है कि चूंकि सीसीएल ने निर्धारित प्रारूप में बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की आवश्यकता में ढील नहीं दी थी या उससे विचलित नहीं किया था, जहां तक वर्तमान अपीलों का संबंध है, प्रत्येक बोलीदाता बैंक गारंटी के निर्धारित प्रारूप का पालन करने के लिए बाध्य था। परिणामस्वरूप, निर्धारित प्रपत्र में बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में जे वीसी की विफलता सीसीएल के लिए अपनी बोली को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त कारण थी।

"

"-ww.doingbusiness.org/rankings (विश्व बैंक समूह)

56. यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि जिस प्रक्रिया से सीसीएल द्वारा निर्णय लिया गया था कि जे वीसी द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, वह किसी भी तरह से त्रुटिपूर्ण था। इसी तरह यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि सीसीएल द्वारा जे वीसी द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी को अस्वीकार करने और एनआईटी और जी टीसी की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए लिया गया निर्णय मनमाना या अनुचित या किसी भी तरह से विकृत था।

57. तद्नुसार झारखण्ड उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय एवं आदेश को रद्द किया जाता है एवं इन अपीलों को अनुमति दी जाती है

देविका गुजराल अपील की अनुमति है।

यह अनुवाद शिव बचन यादव, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।